



IASBABA

One Stop Destination for UPSC/IAS Preparation

60 Days Week-3&4 Compilation



DELHI

BANGALORE

5B, Pusa Road, Karol
Bagh, New Delhi - 110005.
Landmark: Just 50m from
Karol Bagh Metro Station,
GATE No. 8 (Next to
Croma Store)
Ph: 0114167500

#1737/37, MRCR Layout, Vijaynagar
Service Road, Vijaynagar, Bangalore
560040. PH: 09035077800 /
7353277800



support@iasbaba.com



www.iasbaba.com

Q.1) संविधान के संशोधन की प्रक्रिया के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें जैसा कि अनुच्छेद 368 में निर्धारित किया गया है

1. विधेयक के प्रस्ताव को राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति की आवश्यकता होती है।
2. विधेयक को प्रत्येक सदन में पूर्ण बहुमत से पारित किया जाना चाहिए।
3. दोनों सदनों के बीच मतभेद के मामले में, दोनों सदनों की संयुक्त बैठक आयोजित की जाती है।

नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनें

- a) केवल 1
- b) 1 और 2
- c) 2 और 3
- d) उपरोक्त में से कोई नहीं

Q.1) Solution (d)

कथन 1	कथन 2	कथन 3
असत्य	असत्य	असत्य
विधेयक को मंत्री या निजी सदस्य द्वारा प्रस्तुत किया जा सकता है तथा उसे राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति की आवश्यकता नहीं होती है।	प्रत्येक सदन में विधेयक को विशेष बहुमत से पारित किया जाना चाहिए, अर्थात्, सदन की कुल सदस्यता का बहुमत (यानी 50 प्रतिशत से अधिक) तथा वर्तमान में सदन उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का दो-तिहाई बहुमत।	प्रत्येक सदन को पृथक रूप से विधेयक पारित करना होगा। दोनों सदनों के बीच असहमति के मामले में, विधेयक के विचार-विमर्श और पारित होने के लिए दोनों सदनों की संयुक्त बैठक आयोजित करने का कोई प्रावधान नहीं है।

Q.2) निम्नलिखित में से किस प्रावधान के लिए संसद के विशेष बहुमत तथा आधे राज्य विधान सभाओं की सहमति की आवश्यकता है?

1. राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत
2. राष्ट्रपति का चुनाव
3. सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित प्रावधान

नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनें

- a) केवल 1
- b) 1 और 2
- c) 2 और 3
- d) उपरोक्त सभी

Q.2) Solution (c)

कथन 1	कथन 2	कथन 3
असत्य	सत्य	सत्य
मौलिक अधिकार और राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत संविधान में उन प्रावधानों में से हैं जिन्हें संसद के विशेष बहुमत से संशोधित करने की आवश्यकता होती है।	निम्नलिखित प्रावधानों को संसद के एक विशेष बहुमत द्वारा संशोधित किया जा सकता है तथा एक साधारण बहुमत की आधे राज्य विधानसभाओं से सहमति की भी आवश्यकता होती है: 1. राष्ट्रपति का चुनाव और उसके तरीके। 2. संघ और राज्यों की कार्यकारी शक्ति का विस्तार। 3. सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय। 4. संघ और राज्यों के बीच विधायी शक्तियों का वितरण। 5. सातवीं अनुसूची में कोई भी सूची। 6. संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व। 7. संविधान और उसकी प्रक्रिया में संशोधन के लिए संसद की शक्ति (अनुच्छेद 368 स्वयं)।	

Prelims 2020 Exclusive :Current Affairs Classes

Beat the Heat of Current Affairs Prelims 2020 in 12 Uber Cool Sessions by Tauseef Ahmad (One of the Founders of IASbaba)

MOST PROBABLE PRELIMS CURRENT AFFAIRS TOPICS FROM PAST 1.5 YEARS WILL BE COVERED IN 12 SESSIONS

CRISP AND ORGANISED NOTES/CONTENT TO MAKE YOUR REVISION EASIER

Starts 15th April

Q.3) निम्नलिखित कथनों पर विचार करें

1. राज्य विधानसभाएँ संविधान में संशोधन के लिए कभी कोई विधेयक या प्रस्ताव नहीं ला सकती हैं।
2. संविधान में संशोधन करने के लिए संसद की शक्ति की सीमा मिन्वा मिल्स मामले के तहत स्थापित की गई थी।

नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनें

- a) केवल 1
- b) केवल 2
- c) 1 और 2 दोनों
- d) न तो 1 और न ही 2

Q.3) Solution (b)

कथन 1	कथन 2
असत्य	सत्य
संविधान में संशोधन करने की शक्ति संसद में निहित है। इसलिए, संयुक्त राज्य अमेरिका के विपरीत, राज्य विधानसभाएं एक मामले को छोड़कर, संविधान में संशोधन के लिए कोई विधेयक या प्रस्ताव नहीं ला सकती हैं, अर्थात्, राज्यों में विधान परिषदों के निर्माण या उन्मूलन के लिए संसद से अनुरोध करने का प्रस्ताव पारित करना।	मिनर्वा मिल्स मामले में सुप्रीम कोर्ट के अनुसार, “चूंकि संविधान ने संसद सीमित संशोधन शक्ति प्रदान की थी, संसद उस सीमित शक्ति के अभ्यास के अंतर्गत नहीं आ सकती है जो विस्तृत शक्ति को एक पूर्ण शक्ति में बदल देती है। वास्तव में, एक सीमित संशोधन शक्ति संविधान की मूल विशेषताओं में से एक है तथा इसलिए, उस शक्ति की सीमाएं नष्ट नहीं की जा सकती हैं। दूसरे शब्दों में, संसद अनुच्छेद 368 के तहत, अपनी संशोधित शक्ति का विस्तार नहीं कर सकती है, ताकि संविधान को निरस्त करने या कम करने या इसकी बुनियादी विशेषताओं को नष्ट करने का अधिकार प्राप्त हो सके। एक सीमित शक्ति का कार्य उस शक्ति के अभ्यास से नहीं हो सकता है जो सीमित शक्ति को असीमित में बदल देता है। नोट- केशवानंद भारती मामले ने आधारभूत संरचना सिद्धांत को अधिनियमित किया, लेकिन संसद की संशोधित शक्ति पर सीमा को मिनर्वा मिल्स केस द्वारा स्थापित किया गया था।

Q.4) राष्ट्रपति के चुनाव के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें

1. राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य केवल निर्वाचक मंडल में भाग ले सकते हैं।
2. जब कोई विधानसभा भंग होती है, तो सदस्य राष्ट्रपति चुनाव में मतदान करने के लिए योग्य होते हैं, केवल तभी, जब राष्ट्रपति चुनाव से पहले भंग विधानसभा के लिए नए सिरे से चुनाव नहीं हो सकते हैं।

नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनें

- a) केवल 1
- b) केवल 2
- c) 1 और 2 दोनों
- d) न तो 1 और न ही 2

Q.4) Solution (a)

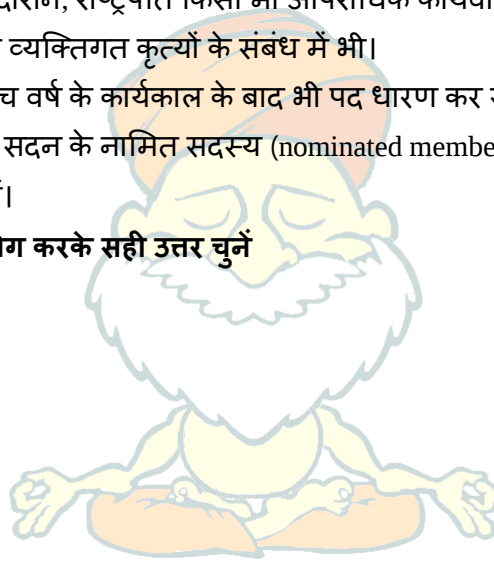
कथन 1	कथन 2
सत्य	असत्य
राष्ट्रपति का चुनाव सीधे लोगों द्वारा नहीं, बल्कि निर्वाचक मंडल के सदस्यों द्वारा किया जाता है: 1. संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य; 2. राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य; तथा 3. केंद्र शासित प्रदेशों दिल्ली और पुदुचेरी की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य।	जहां एक विधानसभा को भंग कर दिया जाता है, वहां के सदस्य राष्ट्रपति चुनाव में मतदान करने के लिए योग्य नहीं होते हैं, भले ही भंग विधानसभा के नए चुनाव राष्ट्रपति चुनाव से पहले न हों।

Q.5) निम्नलिखित कथनों पर विचार करें

1. अपने पदावधि के दौरान, राष्ट्रपति किसी भी आपराधिक कार्यवाही से प्रतिरक्षित रहता है, यहां तक कि अपने व्यक्तिगत कृत्यों के संबंध में भी।
2. राष्ट्रपति अपने पांच वर्ष के कार्यकाल के बाद भी पद धारण कर सकता है।
3. संसद के किसी भी सदन के नामित सदस्य (nominated members) राष्ट्रपति के महाभियोग में भाग नहीं लेते हैं।

नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनें

- a) 1 और 2
- b) 1 और 3
- c) 2 और 3
- d) उपरोक्त सभी



Q.5) Solution (a)

कथन 1	कथन 2	कथन 3
सत्य	सत्य	असत्य
राष्ट्रपति के अपने कार्यकाल के दौरान, राष्ट्रपति किसी भी आपराधिक कार्यवाही से प्रतिरक्षित रहते हैं, यहां तक कि अपने व्यक्तिगत कृत्यों के संबंध में भी।	राष्ट्रपति पांच वर्ष के अपने कार्यकाल के बाद भी तब तक पद संभाल सकते हैं जब तक कि उनके उत्तराधिकारी पदभार नहीं लेते	संसद के दोनों सदनों के नामित सदस्य राष्ट्रपति के महाभियोग में भाग ले सकते हैं

Q.6) राष्ट्रपति की शक्तियों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है?

1. वह किसी भी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित कर सकता है।
2. अनुदान की कोई माँग उसकी अनुशंसा के अलावा नहीं की जा सकती।

3. वह चुनाव आयोग के परामर्श से संसद के सदस्यों की अयोग्यता के रूप में प्रश्नों पर निर्णय लेता है।

नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनें

- 1 और 2
- 1 और 3
- 2 और 3
- उपरोक्त सभी

Q.6) Solution (d)

कथन 1	कथन 2	कथन 3
सत्य	सत्य	सत्य
अपनी कार्यकारी शक्तियों के तहत, वह किसी भी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित कर सकता है तथा अनुसूचित क्षेत्रों और जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में अधिकार रखता है।	उनकी वित्तीय शक्तियों के तहत, उनकी सिफारिश के अलावा अनुदान की कोई मांग नहीं की जा सकती है।	अपनी विधायी शक्तियों के तहत, वह चुनाव आयोग के परामर्श से संसद के सदस्यों की अयोग्यता के रूप में प्रश्नों पर निर्णय लेता है।

Q.7) निरपेक्ष वीटो (Absolute veto) का प्रयोग, निम्नलिखित में से किस मामले में नहीं किया जा सकता है?

- निजी सदस्यों के विधेयक
- संवैधानिक संशोधन विधेयक
- धन विधेयक

नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनें

- 1 और 2
- केवल 2
- केवल 3
- 2 और 3

Q.7) Solution (b)

कथन 1	कथन 2	कथन 3
असत्य	सत्य	असत्य
आमतौर पर, निरपेक्ष वीटो	संवैधानिक संशोधन विधेयक के	राष्ट्रपति या तो धन विधेयक को

(absolute veto) का प्रयोग निम्नलिखित दो मामलों में किया जाता है: (a) निजी सदस्यों के विधेयक के संबंध में (यानी, संसद के किसी भी सदस्य द्वारा प्रस्तुत किए गए विधेयक जो मंत्री नहीं हैं); तथा (b) कैबिनेट के इस्तीफे के बाद (विधेयकों के पारित होने के बाद लेकिन राष्ट्रपति द्वारा सहमति से पहले) सरकारी बिल के संबंध में और नए कैबिनेट राष्ट्रपति को सलाह देते हैं कि वे ऐसे बिलों के लिए अपनी सहमति न दें।	संबंध में राष्ट्रपति के पास वीटो शक्ति नहीं है। 1971 के 24 वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने राष्ट्रपति के लिए संवैधानिक संशोधन विधेयक पर अपनी सहमति देना अनिवार्य कर दिया।	अपनी सहमति दे सकता है या धन विधेयक के लिए अपनी सहमति वापस ले सकता है लेकिन संसद के पुनर्विचार के लिए इसे वापस नहीं कर सकता है। इसका अर्थ है कि धन विधेयक के मामले में राष्ट्रपति के पास कोई भी निलंबनकारी वीटो शक्ति उपलब्ध नहीं है। वह धन विधेयक के मामले में निरपेक्ष वीटो का प्रयोग कर सकते हैं।
--	--	--

Q.8) सुप्रीम कोर्ट ने विभिन्न मामलों के तहत राष्ट्रपति की क्षमा शक्ति की जांच की तथा निम्नलिखित सिद्धांतों को निर्धारित किया। इस संदर्भ में, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है?

1. दया के लिए याचिकाकर्ता को राष्ट्रपति द्वारा मौखिक सुनवाई (oral hearing) का अधिकार है।
2. राष्ट्रपति नए सिरे से साक्ष्यों की जांच कर सकता है तथा न्यायालय द्वारा लिए गए दृष्टिकोण से अलग विचार कर सकता है।
3. राष्ट्रपति अपने आदेश के लिए कारण देने हेतु बाध्य नहीं है।

नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनें

- a) 1 और 2
- b) 1 और 3
- c) 2 और 3
- d) उपरोक्त सभी

Q.8) Solution (c)

कथन 1	कथन 2	कथन 3
असत्य	सत्य	सत्य
उच्चतम न्यायालय ने विभिन्न मामलों के तहत राष्ट्रपति की क्षमा शक्ति की जांच की तथा निम्नलिखित सिद्धांत निर्धारित किए:		

1. दया के लिए याचिकाकर्ता को राष्ट्रपति द्वारा मौखिक सुनवाई का कोई अधिकार नहीं है।
2. राष्ट्रपति नए सिरे से साक्ष्यों की जांच कर सकता है और न्यायालय द्वारा लिए गए दृष्टिकोण से अलग विचार कर सकता है।
3. केंद्रीय मंत्रिमंडल की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा शक्ति का प्रयोग किया जाना है।
4. राष्ट्रपति अपने आदेश के लिए कारण देने के लिए बाध्य नहीं है।
5. राष्ट्रपति न केवल एक ऐसे दंड से राहत दे सकता है जिसे वह अनुचित रूप से कठोर मानता है बल्कि एक स्पष्ट गलती से भी दिए गए को।
6. राष्ट्रपति द्वारा शक्ति के प्रयोग के लिए विशिष्ट दिशानिर्देशों को निर्धारित करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय की कोई आवश्यकता नहीं है।
7. राष्ट्रपति द्वारा शक्ति का प्रयोग न्यायिक समीक्षा के अधीन नहीं है, सिवाय इसके कि राष्ट्रपति का निर्णय मनमाना, तर्कहीन, गैर-कानूनी या भेदभावपूर्ण न हो।

Q.9) निम्नलिखित कथनों पर विचार करें

1. राष्ट्रपति के पास संवैधानिक के साथ-साथ स्थितिजन्य विवेकाधिकार भी हैं।
2. वह प्रधानमंत्री की नियुक्ति में अपने विवेकाधिकार पर कार्य कर सकता है, जब किसी भी दल के पास लोकसभा में स्पष्ट बहुमत नहीं होता है।

नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनें

- a) केवल 1
- b) केवल 2
- c) 1 और 2 दोनों
- d) न तो 1 और न ही 2

Q.9) Solution (b)

कथन 1	कथन 2
असत्य	सत्य
यद्यपि राष्ट्रपति के पास कोई संवैधानिक विवेकाधिकार नहीं है, उनके पास कुछ स्थितिजन्य विवेकाधिकार हैं। दूसरे शब्दों में, राष्ट्रपति अपने विवेकाधिकार से (अर्थात् मंत्रियों की सलाह के बिना) निम्नलिखित स्थितियों में कार्य कर सकते हैं: (i) प्रधानमंत्री की नियुक्ति तब होती है जब किसी भी दल के पास लोकसभा में स्पष्ट बहुमत नहीं होता है या जब कार्यालय में प्रधान मंत्री की अचानक मृत्यु हो जाती है और कोई स्पष्ट उत्तराधिकारी नहीं होता है। (ii) जब वह लोकसभा के विश्वास को प्रमाणित नहीं कर सकता, तो मंत्रिपरिषद का विघटन। (iii) यदि मंत्रिपरिषद ने अपना बहुमत खो दिया है तो लोकसभा का विघटन।	

Q.10) उपराष्ट्रपति के कार्यालय के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें

1. उपराष्ट्रपति का चुनाव एकल हस्तांतरणीय मत के माध्यम से आनुपातिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली के अनुसार होता है।
2. संविधान के अनुसार, उस पर 'संविधान के उल्लंघन' के लिए महाभियोग लगाया जा सकता है।

नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनें

- a) केवल 1
- b) केवल 2
- c) 1 और 2 दोनों
- d) न तो 1 और न ही 2

Q.10) Solution (a)

कथन 1	कथन 2
सत्य	असत्य
उपराष्ट्रपति का चुनाव, राष्ट्रपति के चुनाव की तरह, एकल हस्तांतरणीय वोट के माध्यम से आनुपातिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली के अनुसार आयोजित किया जाता है तथा मतदान गुप्त मतदान द्वारा होता है।	उसके निष्कासन के लिए एक औपचारिक महाभियोग की आवश्यकता नहीं है। उन्हें पूर्ण बहुमत से पारित राज्य सभा के प्रस्ताव के द्वारा हटाया जा सकता है (अर्थात्, सदन के कुल सदस्यों का बहुमत) और लोकसभा द्वारा सहमति व्यक्त की जाती है। लेकिन, जब तक कम से कम 14 दिनों की अग्रिम सूचना नहीं दी जाती है, तब तक इस तरह के किसी भी प्रस्ताव को नहीं लाया जा सकता है। विशेष रूप से, उनके निष्कासन के लिए संविधान में किसी भी आधार का उल्लेख नहीं किया गया है।

Q.11) 'भारतीय संविधान के प्रति सच्चा विश्वास और निष्ठा रखना', निम्नलिखित में से किसकी शपथ का हिस्सा है?

1. राष्ट्रपति
2. प्रधान मंत्री
3. मंत्रिपरिषद्
4. सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश

नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनें

- a) 1,2 और 3
- b) 1,3 और 4
- c) 2,3 और 4
- d) उपरोक्त सभी

Q.11) Solution (c)

कथन 1	कथन 2	कथन 3	कथन 4
असत्य	सत्य	सत्य	सत्य
राष्ट्रपति की शपथ: - कार्यालय को ईमानदारी से निष्पादित करने के लिए; - संविधान और कानून का संरक्षण, सुरक्षा और बचाव करना; तथा - भारत के लोगों की सेवा और कल्याण के लिए स्वयं को समर्पित करना।	प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद् की शपथ - भारत के संविधान के प्रति सच्चा विश्वास और निष्ठा रखना, - भारत की संप्रभुता और अखंडता को बनाए रखना, - ईमानदारी से और कर्तव्यनिष्ठा से अपने कार्यालय के कर्तव्यों का निर्वहन करना, और - बिना किसी भय या पक्ष, स्नेह या दुर्भावना के, संविधान और कानून के अनुसार सभी प्रकार के लोगों को समान अधिकार प्रदान करना।		सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की शपथ: - भारत के संविधान के प्रति सच्चा विश्वास और निष्ठा रखना; - भारत की संप्रभुता और अखंडता को बनाए रखना; - विधिवत और विश्वासपूर्वक और उसकी क्षमता, ज्ञान और निर्णय कार्यालय के कर्तव्यों को बिना किसी डर या पक्ष, स्नेह या दुर्भावना के निभाते हैं; तथा - संविधान और कानूनों को बनाए रखना।

Q.12) प्रधान मंत्री कार्यालय के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें

- संविधान के अनुसार, एक व्यक्ति जो संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं है, उसे छह महीने के लिए प्रधान मंत्री के रूप में नियुक्त किया जा सकता है, जिसके भीतर, उसे संसद के किसी भी सदन का सदस्य बनना चाहिए।
- वह राष्ट्रपति की प्रसाद पर्यन्त पद धारण करता है, इसलिए किसी भी समय राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है।

नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनें

- केवल 1
- केवल 2
- 1 और 2 दोनों
- न तो 1 और न ही 2

Q.12) Solution (d)

कथन 1	कथन 2
-------	-------

असत्य	असत्य
1997 में, सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि जो व्यक्ति संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं है, उसे छह महीने के लिए प्रधान मंत्री के रूप में नियुक्त किया जा सकता है, जिसके भीतर उसे संसद के किसी भी सदन का सदस्य बनना चाहिए; अन्यथा, उसका प्रधान मंत्री पद समाप्त हो जायेगा। नोट- संविधान में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है।	प्रधानमंत्री का कार्यकाल तय नहीं है और वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यन्त के दौरान पद पर रहते हैं। हालांकि, इसका अर्थ यह नहीं है कि राष्ट्रपति किसी भी समय प्रधानमंत्री को हटा सकता है। जब तक प्रधानमंत्री को लोकसभा में बहुमत का समर्थन प्राप्त है, उन्हें राष्ट्रपति द्वारा हटाया नहीं जा सकता है। हालांकि, अगर वह लोकसभा का विश्वास खो देता है, तो उसे इस्तीफा देना चाहिए या राष्ट्रपति उसे हटा सकते हैं।

Q.13) प्रधानमंत्री के कार्यों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है?

- वह राय के अंतर के मामले में राष्ट्रपति को एक मंत्री को बर्खास्त करने की सलाह देता है।
- वह मंत्रियों के वेतन और भत्ते का निर्धारण करता है।
- वह वित्त आयोग के सदस्यों की नियुक्ति करता है।
- वह लोकसभा अध्यक्ष (Speaker) की नियुक्ति के लिए राष्ट्रपति को सलाह देता है।

Q.13) Solution (a)

कथन 1	कथन 2	कथन 3	कथन 4
सत्य	असत्य	असत्य	असत्य
प्रधानमंत्री को केंद्रीय मंत्रिपरिषद के प्रमुख के रूप में निम्नलिखित शक्तियां प्राप्त हैं: 1. वह उन लोगों की सिफारिश करता है जिन्हें राष्ट्रपति द्वारा मंत्री के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। राष्ट्रपति केवल उन व्यक्तियों को मंत्री के रूप में नियुक्त कर सकते हैं जो प्रधानमंत्री द्वारा अनुशंसित हैं। 2. वह मंत्रियों के बीच विभिन्न विभागों का	मंत्रियों के वेतन और भत्ते समय-समय पर संसद द्वारा निर्धारित किए जाते हैं।	वह राष्ट्रपति को भारत के महान्यायवादी, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, UPSC के अध्यक्ष और सदस्यों, चुनाव आयुक्तों, वित्त आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों और ऐसे अन्य महत्वपूर्ण अधिकारियों की नियुक्ति के संबंध में सलाह देता है।	अध्यक्ष (Speaker) का चुनाव लोकसभा द्वारा उसके सदस्यों में से किया जाता है (जैसे उसकी प्रथम बैठक के बाद हो सकता है)।

आवंटन और फेरबदल करता है। 3. वह किसी मंत्री को इस्तीफा देने या राय के अंतर के मामले में उसे हटाने की सलाह देने के लिए कह सकता है। 4. वह मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता करता है और उसके निर्णयों को प्रभावित करता है। 5. वह सभी मंत्रियों की गतिविधियों का मार्गदर्शन, निर्देशन, नियंत्रण और समन्वय करता है। 6. वह पद से इस्तीफा देकर मंत्रिपरिषद के पतन का कारण बन सकता है।			
---	--	--	--

Q.14) 91 वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान प्रस्तुत किया गया था?

- राष्ट्रपति को किसी सलाह पर पुनर्विचार करने के लिए मंत्रिपरिषद की आवश्यकता हो सकती है तथा राष्ट्रपति इस तरह के पुनर्विचार के बाद प्रदान की गई सलाह के अनुसार कार्य करेगा।
- मंत्रिपरिषद में प्रधान मंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या, लोकसभा के कुल सदस्य संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी।
- दलबदल के आधार पर संसद और राज्य विधानसभाओं के सदस्यों को अयोग्य ठहराने का प्रावधान
- लोकसभा और राज्य विधान सभा चुनावों के लिए मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई।

Q.14) Solution (b)

कथन a	कथन b	कथन c	कथन d
असत्य	सत्य	असत्य	असत्य

चालीसवां (40) संशोधन अधिनियम, 1978- पुनर्विचार के लिए कैबिनेट की सलाह हेतु राष्ट्रपति को वापस भेजने का अधिकार। लेकिन, राष्ट्रपति पर पुनर्विचार की सलाह बाध्यकारी होती है।	इक्यानवे (91) संशोधन अधिनियम, 2003- केंद्रीय मंत्रिपरिषद में प्रधान मंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा के कुल सदस्य संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी (अनुच्छेद 75 (1 ए))।	बावनवाँ (52) संशोधन अधिनियम, 1985- दलबदल के आधार पर संसद और राज्य विधानसभाओं के सदस्यों को अयोग्य ठहराने का प्रावधान किया गया और इस संबंध में विवरण सहित एक नई दसवीं अनुसूची जोड़ी गई।	एकसठवां (61) संशोधन अधिनियम, 1989- लोकसभा और राज्य विधान सभा चुनावों के लिए मतदान की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया।
---	--	--	---

Q.15) संघ कार्यकारिणी (union executive) के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें

1. राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह के बिना कार्यकारी शक्ति का प्रयोग नहीं कर सकता।
2. मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है।
3. एक मंत्री जो संसद के एक सदन का सदस्य होता है, उसे दूसरे सदन में मतदान करने और कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार होता है।

नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनें

- a) 1 और 2
- b) 1 और 3
- c) 2 और 3
- d) उपरोक्त सभी

Q.15) Solution (a)

कथन 1	कथन 2	कथन
सत्य	सत्य	असत्य
सर्वोच्च न्यायालय के अनुसार, अनुच्छेद 74 अनिवार्य है तथा इसलिए, राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह के बिना कार्यकारी शक्ति का प्रयोग नहीं कर सकता है।	अनुच्छेद 75 स्पष्ट रूप से बताता है कि मंत्रियों की परिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है इसका अर्थ यह है कि सभी मंत्री अपने सभी कार्य के लिए लोकसभा के प्रति संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं।	एक मंत्री जो संसद के एक सदन का सदस्य होता है, उसे बोलने और दूसरे सदन की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार होता है, लेकिन वह केवल उसी सदन में मतदान कर सकता है, जिसके वह सदस्य हैं।

Q.16) मंत्रिपरिषद में तीन श्रेणी के मंत्री होते हैं, अर्थात् कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, और उप मंत्री। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है?

1. राज्य मंत्रियों को मंत्रालयों / विभागों का स्वतंत्र प्रभार नहीं मिल सकता है।
2. राज्य मंत्री कैबिनेट की बैठकों में भाग नहीं ले सकते, जब तक कि विशेष रूप से आमंत्रित नहीं किया जाता है।
3. उप मंत्री कैबिनेट के सदस्य बन सकते हैं।

नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनें

- a) 1 और 2
- b) 1 और 3
- c) 2 और 3
- d) उपरोक्त सभी

Q.16) Solution (b)

कथन 1	कथन 2	कथन 3
असत्य	सत्य	असत्य
राज्य मंत्रियों को या तो मंत्रालयों / विभागों का स्वतंत्र प्रभार दिया जा सकता है या उन्हें कैबिनेट मंत्रियों से संबद्ध किया जा सकता है।	राज्य मंत्री कैबिनेट के सदस्य नहीं होते हैं तथा कैबिनेट की बैठकों में शामिल नहीं होते हैं जब तक कि विशेष रूप से आमंत्रित नहीं किया जाता है जब उनके मंत्रालयों / विभागों से संबंधित कुछ को कैबिनेट द्वारा माना जाता है।	उप मंत्री कैबिनेट के सदस्य नहीं हैं तथा कैबिनेट की बैठकों में शामिल नहीं होते हैं।

Q.17) 'मंत्रिपरिषद' और 'मंत्रिमंडल' शब्दों का उपयोग अक्सर परस्पर विनिमय के लिए किया जाता है, हालांकि उनके बीच एक निश्चित अंतर है। मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल के बीच अंतर के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है?

1. मंत्रिपरिषद के पास मंत्रिमंडल की तुलना में कोई सामूहिक कार्य नहीं होता है जो आम तौर पर सप्ताह में एक बार बैठक करके जानकारी प्राप्त करता है और सरकारी व्यवसाय के संचालन के बारे में निर्णय लेने के लिए होता है।
2. मंत्रिपरिषद मंत्रिमंडल द्वारा अपने निर्णयों के कार्यान्वयन का पर्यवेक्षण करती है।
3. मंत्रिपरिषद, मंत्रिमंडल की तुलना में मंत्रियों की संख्या के संदर्भ में एक व्यापक निकाय है।

नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनें

- a) 1 और 2
- b) 1 और 3
- c) 2 और 3
- d) उपरोक्त सभी

Q.17) Solution (b)

कथन 1	कथन 2	कथन 3
सत्य	असत्य	सत्य
सरकारी कार्य संचालन हेतु, मंत्रिपरिषद् एक निकाय के रूप में नहीं मिलती है। इसका कोई सामूहिक कार्य नहीं है। कैबिनेट, एक निकाय के रूप में, अक्सर मिलता है तथा जो आम तौर पर सप्ताह में एक बार बैठक करके जानकारी प्राप्त करता है और सरकारी व्यवसाय के संचालन के बारे में निर्णय लेने के लिए होता है। इस प्रकार, इसके सामूहिक कार्य हैं।	मंत्रिमंडल मंत्रिपरिषद् द्वारा अपने निर्णयों के कार्यान्वयन का पर्यवेक्षण करता है।	मंत्रिपरिषद् एक व्यापक निकाय है जिसमें 60 से 70 मंत्री होते हैं। मंत्रिमंडल एक छोटा निकाय है जिसमें 15 से 20 मंत्री होते हैं।

Q.18) कैबिनेट समितियों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें

1. ये व्यापार के नियमों (Rules of Business) के तहत स्थापित किए गए हैं।
2. यदि प्रधान मंत्री किसी समिति का सदस्य है, तो वह सदैव इसकी अध्यक्षता करता है।
3. संसदीय मामलों की समिति की अध्यक्षता वित्त मंत्री करते हैं।

नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनें

- a) 1 और 2
- b) 1 और 3
- c) 2 और 3
- d) उपरोक्त सभी

Q.18) Solution (a)

कथन 1	कथन 2	कथन 3
सत्य	सत्य	असत्य
मंत्रिमंडल समितियाँ अतिरिक्त संवैधानिक हैं। दूसरे शब्दों में, संविधान में उनका उल्लेख नहीं है। हालांकि, व्यापार के नियम उनकी स्थापना के लिए प्रावधान प्रदान करते हैं।	वे ज्यादातर प्रधान मंत्री के नेतृत्व में हैं। कुछ बार अन्य कैबिनेट मंत्री, विशेष रूप से गृह मंत्री या वित्त मंत्री भी इसके अध्यक्ष के रूप में कार्य करते हैं। लेकिन, यदि प्रधान मंत्री किसी समिति का सदस्य होता है, तो	संसदीय मामलों की समिति वर्तमान में रक्षा मंत्री की अध्यक्षता में है।

	वह निश्चित रूप से इसकी अध्यक्षता करता है।	
--	---	--

Q.19) भारत के महान्यायवादी के कार्यालय के लिए योग्यता संबंधी निम्नलिखित कथनों पर विचार करें

1. उसे भारत का नागरिक होना चाहिए।
2. वह राष्ट्रपति के विचार में पाँच वर्षों के लिए किसी उच्च न्यायालय का न्यायाधीश या दस वर्षों के लिए किसी उच्च न्यायालय का अधिवक्ता या एक प्रतिष्ठित न्यायविद रहा होगा।

नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनें

- a) केवल 1
- b) केवल 2
- c) 1 और 2 दोनों
- d) न तो 1 और न ही 2

Q.19) Solution (c)

कथन 1	कथन 2
सत्य	सत्य
महान्यायवादी को एक ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के योग्य हो। दूसरे शब्दों में, वह भारत का नागरिक होना चाहिए तथा वह राष्ट्रपति के विचार में पांच वर्ष के लिए किसी उच्च न्यायालय का न्यायाधीश या दस वर्ष के लिए किसी उच्च न्यायालय का अधिवक्ता या एक प्रतिष्ठित न्यायविद रहा होगा।	

Q.20) भारत के महान्यायवादी के कार्यालय के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें

1. महान्यायवादी उन सभी विशेषाधिकारों और प्रतिरक्षाओं का आनंद लेता है जो संसद के सदस्य के लिए उपलब्ध हैं।
2. अपने निजी कानूनी व्यवहार में, वह भारत सरकार की अनुमति के बिना आपराधिक अभियोगों में आरोपी व्यक्तियों की रक्षा कर सकता है।
3. वह केंद्रीय कैबिनेट का सदस्य है।

नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनें

- a) केवल 1
- b) 1 और 2
- c) 1 और 3
- d) केवल 2

Q.20) Solution (a)

कथन 1	कथन 2	कथन 3
सत्य	असत्य	असत्य
महान्यायवादी उन सभी विशेषाधिकारों और प्रतिरक्षाओं का आनंद लेता है जो संसद के सदस्य के लिए उपलब्ध हैं।	कर्तव्य की किसी भी जटिलता और संघर्ष से बचने के लिए महान्यायवादी पर सीमाएं लगाई जाती हैं। उनमें से एक है, उसे भारत सरकार की अनुमति के बिना आपराधिक मुकदमों में आरोपी व्यक्तियों का बचाव नहीं करना चाहिए।	महान्यायवादी केंद्रीय कैबिनेट का सदस्य नहीं है। सरकारी स्तर पर कानूनी मामलों की देखभाल के लिए केंद्रीय कैबिनेट में एक अलग कानून मंत्री होता है।

Q.21) संसद के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें

1. भारतीय प्रणाली अमेरिकी पैटर्न के समान है जहां राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग है।
2. नौ केंद्र शासित प्रदेशों में से केवल तीन का लोकसभा में प्रतिनिधित्व है।

नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनें

- a) केवल 1
- b) केवल 2
- c) 1 और 2 दोनों
- d) न तो 1 और न ही 2

Q.21) Solution (d)

कथन 1	कथन 2
असत्य	असत्य
भारतीय प्रणाली ब्रिटिश प्रणाली के समान है जहां राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग होता है। अमेरिकी राष्ट्रपति विधायिका का अभिन्न अंग नहीं हैं।	नौ केंद्र शासित प्रदेशों में से केवल तीन (दिल्ली, पुडुचेरी और जम्मू और कश्मीर) का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व है। सभी केंद्र शासित प्रदेशों का लोकसभा में प्रतिनिधित्व है।

Q.22) निम्नलिखित में से किसका संविधान में उल्लेख नहीं है?

- a) मंत्रिमंडल
- b) लाभ का पद
- c) चुनाव आयुक्त
- d) उपरोक्त सभी संविधान में उल्लिखित हैं

Q.22) Solution (d)

संविधान में उपरोक्त तीनों का उल्लेख है।

कथन a	कथन b	कथन c
सत्य	सत्य	सत्य
अनुच्छेद 352 के अनुसार, राष्ट्रपति केवल मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिशों पर आपातकाल लगाएगा।	अनुच्छेद 324 में अन्य चुनाव आयुक्तों का उल्लेख है	अनुच्छेद 102 (1) (ए) और 191 (1) (ए) में लाभ के पद के बारे में वर्णन है।

ONE STOP DESTINATION FOR ALL YOUR CURRENT AFFAIRS NEEDS

UPDATED ON A DAILY BASIS

PRECISE AND CRISP CURRENT AFFAIRS NOTES

NO NEED TO MAKE NOTES FOR CURRENT AFFAIRS

ONE OF ITS KIND COMPENDIUM OF CURRENT AFFAIRS

SUBSCRIBE NOW

The most organized Platform for Current Affairs Preparation.

Highest Hit Ratio in Prelims (Current Affairs)

Highly Recommended by UPSC Toppers - Rank 4, 6, 9, 14, etc.

BABAPEDIA

Q.23) परिसीमन आयोग के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है?

- आयोग का अध्यक्ष सदैव भारत का मुख्य चुनाव आयुक्त होगा।
- आयोग की रिपोर्ट के संबंध में विवाद के मामले में, अपील केवल भारत के राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति के साथ ही उच्चतम न्यायालय में की जा सकती है।

नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनें

- केवल 1
- केवल 2
- 1 और 2 दोनों
- न तो 1 और न ही 2

Q.23) Solution (d)

कथन 1	कथन 2
असत्य	असत्य

परिसीमन आयोग में तीन सदस्य होते हैं: a) केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त किए जाने वाले अध्यक्ष (सर्वोच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश)। b) मुख्य चुनाव आयुक्त या एक चुनाव आयुक्त, मुख्य चुनाव आयुक्त द्वारा पदेन सदस्य के रूप में नामित किया जाता है। c) संबंधित राज्य के राज्य निर्वाचन आयुक्त, पदेन सदस्य के रूप में ही।	भारत में परिसीमन आयोग एक उच्च शक्ति निकाय है, जिसके आदेशों में कानून की शक्ति होती है तथा किसी भी न्यायालय के समक्ष इसे प्रश्न नहीं कहा जा सकता है।
---	--

Q.24) राज्य सभा संसद में राज्य सूची में एक मामले पर कानून बनाने के लिए एक प्रस्ताव पारित कर सकती है। राज्यसभा की इस शक्ति के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें

1. इस तरह के प्रस्ताव को पूर्ण बहुमत (absolute majority) से पारित किया जाना चाहिए।
2. जब तक राज्य इसके समापन के लिए अनुरोध नहीं करते तब तक यह संकल्प अनिश्चित काल तक लागू रहता है।

नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनें

- a) केवल 1
- b) केवल 2
- c) 1 और 2 दोनों
- d) न तो 1 और न ही 2

Q.24) Solution (d)

कथन 1	कथन 2
असत्य	असत्य
यदि राज्यसभा यह घोषणा करती है कि राष्ट्रहित में यह आवश्यक है कि संसद राज्य सूची में किसी मामले पर कानून बनाये, तो संसद उस मामले पर कानून बनाने के लिए सक्षम हो जाती है। इस तरह के प्रस्ताव को उपस्थित और मतदान करने वाले दो-तिहाई सदस्यों (विशेष बहुमत) द्वारा समर्थित होना चाहिए।	प्रस्ताव एक वर्ष तक लागू रहता है; इसे किसी भी समय नवीनीकृत किया जा सकता है लेकिन एक बार में एक वर्ष से अधिक नहीं। प्रस्ताव के समाप्त होने के छह महीने बाद लागू होने वाले कानूनों का प्रभाव समाप्त हो जाता है।

Q.25) संसद के सदस्य के रूप में चुने जाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी अयोग्यताओं को संविधान द्वारा निर्धारित किया गया है?

1. वह संघ या राज्य सरकार के अधीन लाभ का कोई भी पद रखता है

2. वह भारत का नागरिक नहीं है
3. उसे दो या अधिक वर्षों के कारावास के लिए किसी भी अपराध के परिणामस्वरूप दोषी ठहराया गया है

नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनें

- a) 1 और 2
- b) 1 और 3
- c) 2 और 3
- d) उपरोक्त सभी

Q.25) Solution (a)

कथन 1	कथन 2	कथन 3
सत्य	सत्य	असत्य
संविधान के तहत, एक व्यक्ति को संसद के सदस्य के रूप में चुने जाने के लिए अयोग्य घोषित किया जाएगा: - यदि वह संघ या राज्य सरकार (संसद द्वारा मुक्त किसी मंत्री या किसी अन्य कार्यालय को छोड़कर) के तहत किसी भी लाभ का पद धारण करता है। - यदि वह विकृत बुद्धि का है और न्यायालय द्वारा घोषित किया गया है। - यदि वह एक अघोषित दिवालिया है। - यदि वह भारत का नागरिक नहीं है या उसने स्वेच्छा से किसी विदेशी राज्य की नागरिकता प्राप्त कर ली है या किसी विदेशी राज्य के प्रति निष्ठा की किसी भी स्वीकृति के अधीन है; तथा - यदि वह संसद द्वारा बनाए गए किसी कानून के तहत अयोग्य है।		संसद ने जन प्रतिनिधित्व अधिनियम (1951) में निम्नलिखित अतिरिक्त अयोग्यता को निर्धारित किया है: - वह चुनावों में कुछ विशेष अपराधों या भ्रष्ट आचरण का दोषी नहीं पाया गया हो। - उसे दो या अधिक वर्षों के कारावास के लिए किसी भी अपराध के परिणामस्वरूप दोषी ठहराया गया हो। लेकिन, निवारक निरोध कानून के तहत किसी व्यक्ति को हिरासत में लेना अयोग्यता नहीं है। - वह समय के भीतर अपने चुनावी खर्चों का लेखा-जोखा रखने में विफल नहीं रहा हो। - उसका सरकारी अनुबंधों, कार्यों या सेवाओं में कोई हित नहीं होना चाहिए। - वह एक निदेशक या प्रबंध एजेंट नहीं होना चाहिए और न ही एक निगम में लाभ का पद धारण करना चाहिए जिसमें सरकार का कम से कम 25 प्रतिशत हिस्सा हो। - उन्हें भ्रष्टाचार या राज्य के प्रति अनिष्ठा के लिए सरकारी सेवा से

	बर्खास्त नहीं किया गया होगा। 7. उसे विभिन्न समूहों के बीच शत्रुता को बढ़ावा देने या रिश्तों के अपराध के लिए दोषी नहीं ठहराया जाना चाहिए था। 8. अस्पृश्यता, दहेज और सती जैसे सामाजिक अपराधों के प्रचार और अभ्यास के लिए उन्हें दंडित नहीं किया गया हो।
--	--

Q.26) राज्य सभा भारत की संसद का उच्च सदन (द्वितीय चेंबर) है, जो भारतीय संघ के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करता है। संसद के उच्च सदन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है / हैं?

1. राज्यसभा का गठन पहली बार 26 जनवरी 1950 को किया गया था।
2. संविधान ने राज्यसभा के सदस्यों के पद का कार्यकाल छह वर्ष निर्धारित किया है।
3. राज्यसभा में सीटों का आवंटन, संयुक्त राज्य अमेरिका की सीनेट के समान है।

नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनें

- a) 1 और 2
- b) 2 और 3
- c) केवल 3
- d) उपरोक्त सभी

Q.26) Solution (d)

कथन 1	कथन 2	कथन 3
असत्य	असत्य	असत्य
1952 में राज्यसभा पहली बार गठित की गई थी।	संविधान ने राज्य सभा के सदस्यों के कार्यालय का कार्यकाल तय नहीं किया है इसे संसद के लिए इसे छोड़ दिया। तदनुसार, संसद में जनप्रतिनिधित्व अधिनियम (1951) में यह प्रावधान है कि राज्य सभा के सदस्य के पद का कार्यकाल छह वर्ष का होगा।	राज्यसभा में जनसंख्या के आधार पर राज्यों को सीटें आवंटित की जाती हैं। इसलिए, प्रतिनिधियों की संख्या राज्य से अलग-अलग होती है। संयुक्त राज्य अमेरिका में, सभी राज्यों को उनकी आबादी के बावजूद सीनेट में समान प्रतिनिधित्व दिया जाता है। संयुक्त राज्य अमेरिका में 50

		राज्य हैं और प्रत्येक राज्य से सीनेट के 100 सदस्य हैं।
--	--	--

Q.27) लोकसभा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें

1. लोक सभा की उत्पत्ति 1853 के चार्टर अधिनियम से की जा सकती है।
2. लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 550 तय की गई है।
3. प्रधान मंत्री सदैव लोकसभा के लिए सदन के नेता के रूप में कार्य करते हैं।

नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही कथन चुनें

- a) केवल 1
- b) 2 और 3
- c) 1 और 3
- d) उपरोक्त सभी

Q.27) Solution (a)

कथन 1	कथन 2	कथन 3
सत्य	असत्य	असत्य
1853 के चार्टर एक्ट में लोकसभा की उत्पत्ति का पता लगाया जा सकता है। 1853 के चार्टर एक्ट ने पहली बार 12 सदस्यीय विधान परिषद के रूप में सीमित विधायिका प्रदान की।	लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 552 पर निर्धारित है। इसमें से 530 सदस्य राज्यों के प्रतिनिधि हैं, 20 सदस्य केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधियों और 2 सदस्यों को एंग्लो-इंडियन समुदाय से राष्ट्रपति द्वारा नामित किया जाना है	प्रधान मंत्री 'सदन के नेता' के रूप में कार्य करता है, यदि वह लोकसभा का सदस्य है, अन्यथा वह मंत्री जो लोकसभा का सदस्य है और प्रधानमंत्री द्वारा नामित किया जाता है, 'सदन के नेता' के रूप में कार्य करता है।

Q.28) लोकसभा अध्यक्ष के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें

1. वह मत बराबर होने के मामले में एक निर्णायक मत डालता है।
2. वह सदन में मतदान नहीं कर सकता है जब उसके निष्कासन का प्रस्ताव सदन में विचाराधीन हो।
3. वह लोकसभा के विघटन के बाद भी अपने पद पर बने रहते हैं।

नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही कथन चुनें

- a) केवल 1
- b) 2 और 3
- c) 1 और 3
- d) उपरोक्त सभी

Q.28) Solution (c)

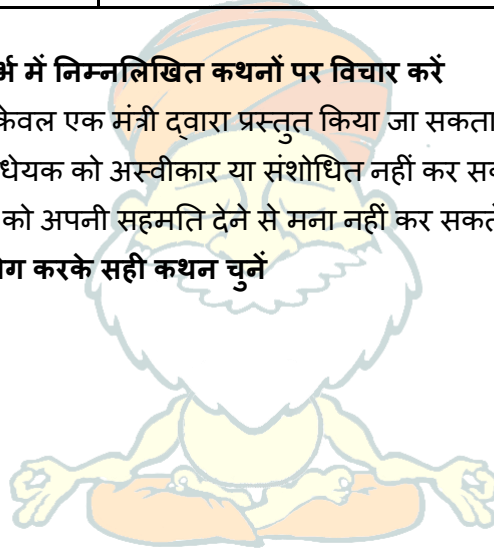
कथन 1	कथन 2	कथन 3
सत्य	असत्य	सत्य
आम तौर पर, अध्यक्ष पहली बार में वोट नहीं करता है। लेकिन वह बराबर मत होने के मामले में एक निर्णायक मत डाल सकता है।	जब अध्यक्ष को हटाने का प्रस्ताव सदन के विचाराधीन होता है, तो वह सदन के बैठक में अध्यक्षता नहीं कर सकता, हालांकि वह उपस्थित हो सकता है। हालांकि, वह ऐसे समय में सदन की कार्यवाही में भाग ले सकते हैं तथा पहली बार में मतदान कर सकते हैं, हालांकि वोटों की समानता के मामले में नहीं।	जब भी लोकसभा को भंग किया जाता है, अध्यक्ष अपना पद नहीं छोड़ता है तथा तब तक जारी रखता है जब तक कि नव-निर्वाचित लोकसभा की पहली बैठक नहीं हो जाती।

Q.29) धन विधेयक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें

1. एक धन विधेयक केवल एक मंत्री द्वारा प्रस्तुत किया जा सकता है।
2. राज्य सभा धन विधेयक को अस्वीकार या संशोधित नहीं कर सकती है।
3. राष्ट्रपति विधेयक को अपनी सहमति देने से मना नहीं कर सकते हैं।

नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही कथन चुनें

- a) 1 और 2
- b) 1 और 3
- c) 2 और 3
- d) उपरोक्त सभी



Q.29) Solution (a)

कथन 1	कथन 2	कथन 3
सत्य	सत्य	असत्य
संविधान का अनुच्छेद 110 धन विधेयकों की परिभाषा से संबंधित है। इस तरह के हर विधेयक को सरकारी विधेयक माना जाता है और इसे केवल एक मंत्री द्वारा ही प्रस्तुत किया जा सकता है।	राज्यसभा ने धन विधेयक के संबंध में शक्तियों को प्रतिबंधित कर दिया है। यह धन विधेयक को अस्वीकार या संशोधित नहीं कर सकती है।	जब एक धन विधेयक राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है, तो वह या तो विधेयक को अपनी सहमति दे सकता है या विधेयक के लिए अपनी सहमति रोक सकता है, लेकिन सदनों के पुनर्विचार के लिए विधेयक वापस नहीं कर सकता है।

Q.30) बजट के अधिनियमन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक प्रावधान गलत है?

- संसद कर बढ़ा नहीं सकती है।
- राज्य सभा अनुदान की माँग पर मतदान नहीं कर सकती।
- एक धन विधेयक के विपरीत, कराधान से संबंधित एक वित्त विधेयक राज्यसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है।
- कानून के अधिकार को छोड़कर कोई कर नहीं लगाया जाएगा।

Q.30) Solution (c)

कथन 1	कथन 2	कथन 3	कथन 4
सत्य	सत्य	असत्य	सत्य

भारत के संविधान में बजट के अधिनियमन के संबंध में निम्नलिखित प्रावधान हैं:

- राष्ट्रपति प्रत्येक वित्तीय वर्ष के संबंध में संसद के दोनों सदनों के समक्ष भारत सरकार के अनुमानित प्राप्तियों और व्यय का विवरण देने के लिए निर्धारित किया जाएगा।
- राष्ट्रपति की सिफारिश के अलावा अनुदान की कोई माँग नहीं की जाएगी।
- कानून द्वारा किए गए विनियोग के अतिरिक्त भारत के समेकित कोष से कोई धन नहीं निकाला जाएगा।
- कर लगाने वाला कोई भी धन विधेयक संसद में राष्ट्रपति की सिफारिश के अतिरिक्त प्रस्तुत नहीं किया जाएगा, तथा ऐसा बिल राज्य सभा में प्रस्तुत नहीं किया जाएगा।
- कानून के अधिकार के अलावा कोई कर नहीं लगाया जाएगा या एकत्र नहीं किया जाएगा।
- संसद एक कर को कम या समाप्त कर सकती है लेकिन इसे बढ़ा नहीं सकती है।
- संविधान ने संसद के दोनों सदनों की सापेक्ष भूमिकाओं या स्थिति को बजट के अधिनियमन के संबंध में निम्न प्रकार से परिभाषित किया है:
 - कराधान से संबंधित धन विधेयक या वित्त विधेयक राज्यसभा में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है - इसे केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जाना चाहिए।
 - राज्य सभा को अनुदान की माँग पर मतदान करने की कोई शक्ति नहीं है; यह लोकसभा का विशेष विशेषाधिकार है।
 - राज्यसभा को धन विधेयक (या वित्त विधेयक) को चौदह दिनों के भीतर लोकसभा में वापस करना चाहिए। लोकसभा इस संबंध में राज्यसभा द्वारा की गई सिफारिशों को स्वीकार या अस्वीकार कर सकती है।
- बजट में सन्निहित व्यय के अनुमान भारत के समेकित कोष पर भारित तथा भारत के समेकित कोष से किए गए व्यय को अलग-अलग दर्शाएंगे।
- बजट राजस्व खाते पर व्यय को अन्य व्यय से अलग करेगा।
- भारत के समेकित कोष पर भारित व्यय संसद में मत के लिए प्रस्तुत नहीं किया जाएगा। हालाँकि, इस पर संसद में चर्चा की जा सकती है।

Q.31) राष्ट्रपति चुनाव में मतदान का अधिकार एक है

- प्राकृतिक अधिकार
- संवैधानिक अधिकार
- मौलिक अधिकार
- वैधानिक अधिकार

Q.31) Solution (d)

संवैधानिक अधिकार वे हैं जिनका संविधान में स्पष्ट उल्लेख किया गया है।

अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति चुनाव और निर्वाचक मंडल के सदस्यों के बारे में उल्लेख किया गया है, लेकिन उनके वोट के अधिकार के बारे में नहीं। जनप्रतिनिधित्व कानून के तहत इस पर ध्यान दिया जाता है। तो यह एक वैधानिक अधिकार है।

Q.32) राज्यसभा चुनाव के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है / हैं?

- लोक सभा चुनावों में गुप्त मतपत्रों के उपयोग के विपरीत, राज्यसभा चुनावों में खुले मतपत्रों का उपयोग किया जाता है।
- लोकसभा चुनावों की तरह ही, राज्यसभा चुनावों में भी NOTA (उपरोक्त में से कोई नहीं) विकल्प के उपयोग की अनुमति है।

नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनें

- केवल 1
- केवल 2
- 1 और 2 दोनों
- न तो 1 और न ही 2

Q.32) Solution (a)

कथन 1	कथन 2
सत्य	असत्य
लोकसभा के आम चुनावों के विपरीत, जो गुप्त मतपत्रों (या वोटों) के साथ आयोजित किए जाते हैं और बहुमत के सिद्धांत (first past the post principle) के आधार पर होते हैं, राज्यसभा चुनाव में खुले मतपत्र उपयोग किए जाते हैं। ये चुनाव एकल हस्तांतरणीय मत के आधार पर आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली का पालन करते हैं।	चुनाव आयोग ने उच्चतम न्यायालय के निर्देश के बाद राज्यसभा और विधान परिषद चुनावों के मतदान पत्रों में से (NOTA) विकल्प को समाप्त ले लिया है।

Q.33) 'सचेतक के कार्यालय' (office of whip) के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें।

1. सदन के नियमों में 'सचेतक' के कार्यालय का उल्लेख किया गया है।
2. सचेतक की अवधारणा एक भारतीय नवाचार है।
3. कुछ मामले हैं जैसे कि राष्ट्रपति चुनाव जहां सचेतक एक संसद सदस्य (सांसद) या विधान सभा के सदस्य (विधायक) को किसी विशेष पक्ष में मतदान करने का निर्देश नहीं दे सकते।

नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही कथन चुनें

- a) 1 और 2
- b) केवल 2
- c) केवल 3
- d) 2 और 3

Q.33) Solution (c)

कथन 1	कथन 2	कथन 3
असत्य	असत्य	सत्य
'सचेतक' के कार्यालय का उल्लेख न तो भारत के संविधान में है और न ही सदन के नियमों में और न ही संसदीय कानून में। यह संसदीय सरकार के कन्वेंशन पर आधारित है।	भारत को ब्रिटिश संसदीय प्रणाली से सचेतक की अवधारणा विरासत में मिली।	ऐसे कुछ मामले हैं जैसे कि राष्ट्रपति चुनाव जहां सचेतक एक संसद सदस्य (सांसद) या विधान सभा के सदस्य (विधायक) को किसी खास पक्ष में मतदान करने का निर्देश नहीं दे सकते।

Q.34) संसद के सत्रों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है?

1. सदन की पहली बैठक और उसके सत्रावसान के बीच की अवधि को 'अवकाश' कहा जाता है।
2. स्थगन की शक्ति सदन के पीठासीन अधिकारी के पास है जबकि अनिश्चित कालीन स्थगन के लिए, यह शक्ति राष्ट्रपति के पास होती है।
3. सत्रावसान सदन के समक्ष लंबित विधेयक या किसी अन्य व्यवसाय को समाप्त कर देता है।

नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही कथन चुनें

- a) 1 और 2
- b) 1 और 3
- c) 2 और 3
- d) उपरोक्त सभी

Q.34) Solution (d)

कथन 1	कथन 2	कथन 3
असत्य	असत्य	असत्य

संसद का एक 'सत्र' किसी सदन के पहली बैठक और उसके सत्रावसान (या लोकसभा के मामले में विघटन) के बीच फैली अवधि है। एक सत्र के दौरान, सदन प्रतिदिन कार्यसंचालन को पूरा करता है। एक नए सत्र में किसी सदन के सत्रावसान और उसके पुनः मिलने के बीच की अवधि को 'अवकाश' कहा जाता है।	स्थगन के साथ-साथ अनिश्चित कालीन स्थगन की शक्ति सदन के पीठासीन अधिकारी के पास होती है।	सत्रावसान सदन के समक्ष लंबित विधेयक या किसी अन्य व्यवसाय को प्रभावित नहीं करता है। हालांकि, अगले सत्र के लिए सभी लंबित नोटिस (बिल प्रस्तुत करने के अलावा अन्य) को सत्रावसान में समाप्त हो जाती है। ब्रिटेन में, सत्रावसान सभी बिलों या सदन के समक्ष लंबित किसी अन्य व्यवसाय को समाप्त कर देती है।
--	---	---

Q.35) निम्नलिखित में से कौन सा विधेयक लोकसभा के भंग होने पर समाप्त नहीं होता है?

1. एक विधेयक जो लोकसभा में लंबित है
2. एक विधेयक जो राज्यसभा में लंबित है लेकिन लोकसभा द्वारा पारित नहीं किया गया है
3. एक विधेयक जो लोकसभा द्वारा पारित किया गया था लेकिन राज्यसभा में लंबित है
4. दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक लेकिन राष्ट्रपति द्वारा सदनों को पुनर्विचार के लिए लौटाया गया है

नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही कथन चुनें

- a) 1,2 और 3
- b) 2 और 4
- c) 3 और 4
- d) 1,3 और 4

Q.35) Solution (b)

कथन 1	कथन 2	कथन 3	कथन 4
असत्य	सत्य	असत्य	सत्य

लोक सभा के विघटन पर बिलों के समापन के संबंध में स्थिति निम्नानुसार है:

1. लोक सभा में लंबित एक विधेयक (चाहे वह लोकसभा में उत्पन्न हो या राज्यसभा द्वारा प्रेषित हो)।
2. लोकसभा द्वारा पारित एक विधेयक, लेकिन राज्यसभा में लंबित है।
3. असहमति के कारण दोनों सदनों द्वारा पारित नहीं किया गया एक विधेयक तथा यदि राष्ट्रपति ने लोकसभा के विघटन से पहले संयुक्त बैठक के आयोजन को अधिसूचित किया है, तो समाप्त नहीं होता है।
4. राज्यसभा में लंबित एक विधेयक, लेकिन लोकसभा द्वारा अभी पारित नहीं हुआ विधेयक समाप्त नहीं होगा।
5. दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक, लेकिन राष्ट्रपति की सहमति हेतु लंबित विधेयक समाप्त नहीं होता है।
6. दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक लेकिन राष्ट्रपति द्वारा सदनों के पुनर्विचार के लिए लौटाया गया विधेयक

समाप्त नहीं होता है।

Q.36) संसद में प्रश्नकाल के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें

1. तारांकित प्रश्न के लिए एक मौखिक उत्तर की आवश्यकता होती है तथा पूरक प्रश्न नहीं पूछे जा सकते हैं।
2. एक अतारांकित प्रश्न के लिए लिखित उत्तर की आवश्यकता होती है तथा पूरक प्रश्न नहीं पूछे जा सकते हैं।

नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनें

- a) केवल 1
- b) केवल 2
- c) 1 और 2 दोनों
- d) न तो 1 और न ही 2

Q.36) Solution (b)

कथन 1	कथन 2
असत्य	सत्य
तारांकित प्रश्न (तारांकन द्वारा प्रतिष्ठित) के लिए एक मौखिक उत्तर की आवश्यकता होती है तथा इसलिए पूरक प्रश्नों को पूछा जा सकता है।	एक अतारांकित प्रश्न के लिए लिखित उत्तर की आवश्यकता होती है तथा इसलिए, पूरक प्रश्नों को नहीं पूछा जा सकता है।

Q.37) संसदीय कार्यवाही के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है / हैं?

1. प्रत्येक संसदीय बैठक का पहला घंटा शून्य काल के लिए रखा गया है।
2. प्रश्नकाल के विपरीत, प्रक्रिया के नियमों (Rules of Procedure) में शून्य काल का उल्लेख किया गया है।

नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही कथन चुनें

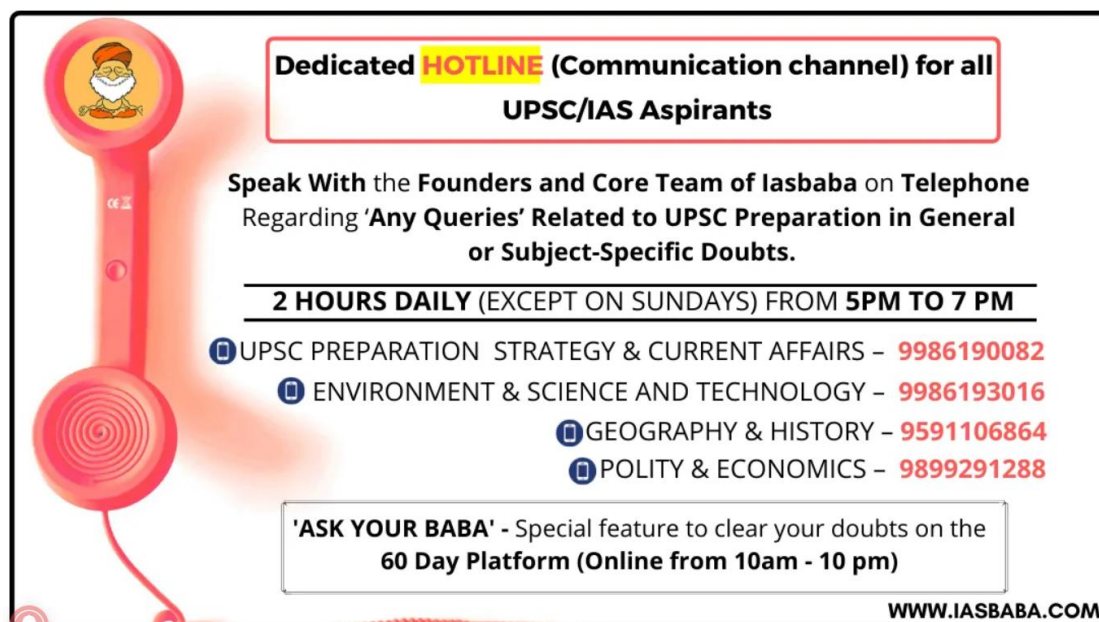
- a) केवल 1
- b) केवल 2
- c) 1 और 2 दोनों
- d) न तो 1 और न ही 2

Q.37) Solution (c)

कथन 1	कथन 2
असत्य	असत्य

प्रत्येक संसदीय बैठक का पहला घंटा प्रश्नकाल के लिए रखा गया है।

प्रश्नकाल के विपरीत, प्रक्रिया के नियमों में शून्य काल का उल्लेख नहीं किया गया है। इस प्रकार यह बिना किसी पूर्व सूचना के मामलों को उठाने के लिए संसद के सदस्यों के लिए एक अनौपचारिक उपकरण है।



Dedicated **HOTLINE (Communication channel) for all UPSC/IAS Aspirants**

Speak With the Founders and Core Team of Iasbaba on Telephone Regarding 'Any Queries' Related to UPSC Preparation in General or Subject-Specific Doubts.

2 HOURS DAILY (EXCEPT ON SUNDAYS) FROM 5PM TO 7 PM

- UPSC PREPARATION STRATEGY & CURRENT AFFAIRS - **9986190082**
- ENVIRONMENT & SCIENCE AND TECHNOLOGY - **9986193016**
- GEOGRAPHY & HISTORY - **9591106864**
- POLITY & ECONOMICS - **9899291288**

'ASK YOUR BABA' - Special feature to clear your doubts on the 60 Day Platform (Online from 10am - 10 pm)

WWW.IASBABA.COM

Q.38) निम्नलिखित में से कौन संसद के सदस्य की दलबदल के आधार पर अयोग्यता के प्रश्न निर्णय लेता है?

- a) भारत के राष्ट्रपति
- b) चुनाव आयोग
- c) सर्वोच्च न्यायालय
- d) सदन के पीठासीन अधिकारी

Q.38) Solution (d)

दसवीं अनुसूची के तहत अयोग्यता के प्रश्न पर निर्णय लोकसभा के मामले में अध्यक्ष द्वारा और राज्यसभा के मामले में सभापति द्वारा लिया जाता है (और भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं)।

Q.39) निम्नलिखित कथनों पर विचार करें

1. संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों के लिए निर्वाचकों का पंजीकरण
2. संसद की सदस्यता के लिए योग्यता और अयोग्यता
3. राजनीतिक दलों का पंजीकरण
4. चुनाव संबंधी विवाद

उपर्युक्त में से कौन सा प्रावधान जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 में मौजूद है?

- a) 1,2 और 3

- b) 1,3 और 4
c) 2,3 और 4
d) उपरोक्त सभी

Q.39) Solution (c)

कथन 1	कथन 2	कथन 3	कथन 4
असत्य	सत्य	सत्य	सत्य
जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों तथा विधानसभा और परिषद निर्वाचन क्षेत्रों के लिए मतदाताओं के पंजीकरण के लिए प्रदान किया गया, और इस तरह के पंजीकरण के लिए योग्यता और अयोग्यता।	जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 में निम्नलिखित चुनावी मामलों से संबंधित प्रावधान शामिल हैं: 1. संसद और राज्य विधानसभाओं की सदस्यता के लिए योग्यता और अयोग्यता 2. आम चुनाव की अधिसूचना 3. चुनाव के संचालन के लिए प्रशासनिक मशीनरी 4. राजनीतिक दलों का पंजीकरण 5. चुनाव का संचालन 6. मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के उम्मीदवारों को कुछ सामग्री की मुफ्त आपूर्ति 7. चुनाव को लेकर विवाद 8. भ्रष्ट आचरण और चुनावी अपराध		

Q.40) निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति एक राजनीतिक दल को राष्ट्रीय पार्टी के रूप में मान्यता देने के योग्य बनाती है?

- यदि यह चार या उससे अधिक राज्यों में लोक सभा के लिए एक आम चुनाव में मतदान किए गए वैध मतों में से छह प्रतिशत प्राप्त करता है तथा इसके अलावा, यह राज्य की किसी भी लोकसभा से दो सीटें जीतता है।
- यदि यह आम चुनाव में लोकसभा की दो प्रतिशत सीटें जीतता है तथा ये उम्मीदवार तीन राज्यों से चुने जाते हैं
- यदि इसे चार राज्यों में राज्य पार्टी के रूप में मान्यता प्राप्त है।

नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही कथन चुनें

- a) 1 और 2
b) 1 और 3
c) 2 और 3
d) उपरोक्त सभी

Q.40) Solution (c)

कथन 1	कथन 2	कथन 3
-------	-------	-------

असत्य	सत्य	सत्य
यदि निम्न में से कोई भी शर्त पूरी हो जाती है, तो एक पार्टी को एक राष्ट्रीय पार्टी के रूप में मान्यता दी जाती है: 1. यदि यह लोकसभा या विधान सभा के आम चुनाव में किसी भी चार या अधिक राज्यों में मतदान किए गए छह प्रतिशत वैध मतों को प्राप्त करता है; तथा, इसके अलावा, यह किसी भी राज्य या राज्यों से लोकसभा में चार सीटें जीतता है; या 2. यदि यह आम चुनाव में लोकसभा की दो प्रतिशत सीटें जीतता है; और ये उम्मीदवार तीन राज्यों से चुने गए हैं; या 3. यदि इसे चार राज्यों में राज्य पार्टी के रूप में मान्यता प्राप्त है।		

Copyright © by IASbaba

All rights are reserved. No part of this document may be reproduced, stored in a retrieval system or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without prior permission of IASbaba.

